THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) With a view to reducing over-crowding of prisoners in Tihar Jail, the Delhi Administration have taken the following steps:

(i) A new ward is under construction in Jail No. 3 to house additional 350 prisoners.

(ii) Two new jails of 700 capacity each are to be constructed in Jail farm area.

(iii) 78.63 acres of land has been acquired for construction of a modern jail in Mandoli (Trans-Yamuna).

(d) and (e) There is no such proposal under consideration of Delhi Administration at present.

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त आयोग

1834. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ऐसे कितने आयोग हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है तथा उनको सौंपे गए काम तथा उनकी नियुक्ति की तारीखें क्या-क्या हैं ; और

(ख) जांच कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन क पटल पर रख दी जाएगी ।

Harassment of women in Lajpat Nagar Police Station

1835. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any action against the Police Officer of the Lajpat Nagar Police Station who harassed a woman and compelled her to join a call girl racket in the last week of April, 92;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the remedial measures Government propose to take to weed out Delhi Police personnel who are having liaison with criminals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) The concerned Sub-Inspector has been removed from service. Departmental enquiry has been ordered against the then SHO/ Lajpat Nagar, New Delhi.

(c) Stern disciplinary action is taken against police personnel having links with criminals. The Vigilance Branch of Delhi Police also maintains a discreet watch in this regard.

ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण तथा उनकी ढुलाई

1836. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण एवं उनकी ढुलाई के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल, 1992 के "दि टाइम्स आंफ इंडिया" में "नो रूल्स, रेग्यूलेशंस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ज्वलनशील मदों के भंडारण/

व्यापार के ला सेंसों के लिए प्रस्तावों की जांच मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट की गई भूमि के अनुसार की जाती है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में, ज्वलनशील मदों के भंडारण/व्यापार के लिए मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद और लाइसेंस में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार ही लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ये क्षेत्र असमान क्षेत्रों में पड़ सकते हैं ऐसे लाइसेंस स्थानीय वाणिज्यिक घोषित किए गए क्षेत्रों के संबंध में भीग जारी किए जाते हैं।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की संवेदनशील स्थिति

1837. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राम-जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद के ढांचे की संवेदनशील स्थिति के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल, 1992 के 'दी टाइम्स आफ इंडिया में, "डिफेंस आफ अयोध्या श्राइन क्म्बहिंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय काय मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी लंबित मामले

1838. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या गृह मंत्री 29 अप्रैल, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 232 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने संबंधी कितने मामले गत तीन, दो और एक वर्ष से अलग अलग लंबित पड़े हुए हैं ; और

(ख) सरकार पेंशन के इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1992 को उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन प्रदान करने के लिए प्राप्त सभी 57 मामले एक वर्ष से कम अवधि के हैं। इन पेंशन मामलों के त्वरित निपटान के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

Exclusion of Pakistan occupied Kashmir from India's Map

1839. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the April 20, issue of the "Times Magazine" which features a map of India without the Pakistan-occupied Kashmir; and

(b) if so, what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) Government's attention has been drawn to the map in question. The matter is under examination.